वर्ष 46 अंक 2
29 फरवरी 2016

मेवाड़ चेम्बर पत्रिका

(मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री का मासिक पत्र)

उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़
राजसमन्द एवं भीलवाड़ा का सम्भागीय चेम्बर

आम बजट प्रस्तुत करने जाते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली अपनी टीम के साथ।

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
मेवाड़ चेम्बर भवन, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा (राज.) 311 001 फोन : 01482-220908, 238948
Email : mcci@mccibhilwara.com Visit us : www.mccibhilwara.com

पुर्ननिर्वाचित अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका का मार्ल्यापण करते हुए
पूर्वाध्यक्ष डॉ. पी एम बेसवाल।

पुर्ननिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा का मार्ल्यापण करते हुए
श्री पी एस तलेसरा।

बांये से दांये – संयुक्त सचिव श्री आर के जैन, उपाध्यक्ष श्री जे के बागड़ोदिया
अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका, मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी, वरिष्ठ
उपाध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा, मानद अंकेक्षक श्री अतुल सोमाणी।

पूर्वाध्यक्ष श्री आर एल नौलखा को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इन्स्टीट्यूट
ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया का वर्ष 2015 का आइकन ऑफ ईयर
अवार्ड प्रदान करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली।

MEWAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Mewar Chamber Bhawan, Nagori Garden
Bhilwara 311 001 (Raj.) ✆ 01482-220908 Fax : 01482-238948
✉ mcci@mccibhilwara.com 🌐 www.mccibhilwara.com

OFFICE BEARERS

	OFFICE	MOBILE
President Mr. Anil Mansinghka anil@shardagroup.net	01482-233800	98290-46101
Sr. Vice President Mr. Dinesh Nolakha dinesh@nitinspinners.com	01482-286111	98281-48111
Vice Presidents Mr. N. N. Jindal jindalmarblepl@gmail.com	01472-240148	94147-34834
Mr. J. K. Bagrodia jkbagrodia1@gmail.com	01482-242435	94141-10754
Mr. P. K. Jain praveen.jain@vedanta.co.in	01483-229011	99280-47578

	OFFICE	MOBILE
Hony. Secretary General Mr. S.P. Nathany mcci@mccibhilwara.com	220908, 238948	94141-12108
Hony. Joint Secretary Mr. R. K. Jain rkjainbhilwara@gmail.com	01482-225844	94141-10844
Hony. Treasurer Mr. Deepak Agarwal deepak@babacollection.com	01482-241600	98290-67400
Executive Officer Mr. M.K.Jain mcci@mccibhilwara.com	220908	94141-10807

AFFILIATION

At the International Level : International Chamber of Commerce, Paris (France)

At the National Level : Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry, (FICCI) New Delhi
Indian Council of Arbitration, New Delhi
National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), New Delhi.
Confederation of All India Traders, New Delhi

At the State Level : Rajasthan Chamber of Commerce & Industry, Jaipur.
: The Employers Association of Rajasthan, Jaipur.
: Rajasthan Textile Mills Association, Jaipur

REPRESENTATION IN NATIONAL & STATE LEVEL COMMITTEES

All India Power loom Board, Ministry of Textile, Govt. of India, New Delhi
National Coal Consumer Council, Coal India Ltd., Kolkata
State Level Tax Advisory Committee, Govt. of Rajasthan, Jaipur
State Level Industrial Advisory Committee, Govt. of Rajasthan, Jaipur
Regional Advisory Committee, Central Excise, Jaipur
Foreign Trade Advisory Committee, Public Grievance Committee, Customs, Jaipur
DRUCC/ZRUCC of North Western Railways

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भीलवाडा

45वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 20.02.2016 की कार्यवाही रिपोर्ट

मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की 45वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 20.02.2016 को सायं 4.00 बजे मेवाड़ चेम्बर भवन, नागोरी गार्डन, भीलवाडा में आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता चेम्बर के अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका ने की।

एजेण्डा आइटम के प्रथम बिन्दु वर्ष 2014–2015 के अंकेक्षित लेखा–जोखा पास करने हेतु प्रस्तुत किये गये। श्री एस पी नाथानी ने कहा कि वर्ष 2014–2015 के अंकेक्षित लेखा–जोखा वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आपको प्रेषित किये गये थे, आशा है आपने अवलोकन किया होगा। किसी सदस्य की कोई टिप्पणी हो तो आमंत्रित है। तत्पश्चात् श्री आर एस जैथलिया ने अंकेक्षित लेखा–जोखा पारित करने का प्रस्ताव रखा एवं श्री के सी प्रहलादका के समर्थन के साथ सर्वसम्मति से अंकेक्षित लेखा–जोखा पारित किये गये।

श्री एस पी नाथानी ने वर्ष 2014–2015 में चेम्बर के मानद ऑडिटर के रुप में अपनी सेवाये देने के लिये एस डाड एण्ड कम्पनी के प्रति आभार का प्रस्ताव रखा, जिसको सभी सदस्यों ने अनुमोदित किया। वर्ष 2015–2016 के लिये मानद ऑडिटर के लिए श्री एस पी नाथानी ने मेसर्स ए के सोमाणी एण्ड एसोसियेट्स को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। जिसका समर्थन श्री पी एस तलेसरा ने किया एवं सभी सदस्यों की सहमति से मेसर्स ए के सोमाणी एण्ड एसोसियेट्स को वर्ष 2015–2016 के लिये मानद ऑडिटर नियुक्त किया गया।

प्रबंधकारणी समिति के गठन के विषय में श्री अनिल मानसिंहका ने चुनाव अधिकारी श्री ए के दुग्गड के आवश्यक कार्य से बाहर होने से सहायक अधिकारी श्री एम के जैन अपनी रिपोर्ट को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति में वर्ष 2016 के लिये संविधान अनुसार स्वतः चयनित प्रथम 20 एसोसियेट सदस्य एवं 20 सदस्य इस वर्ष रोटेशन अनुसार आये है जिनके नाम सदस्यों को वार्षिक बैठक के पत्र के साथ भेजे गये थे, जो कि निम्नानुसार है :–

List of Associate Members who will be automatically be the Members of the Managing Committee 2016

Sr.	F.N.	Members Name	Representative
1	1	Birla Corporation Ltd.	Shri V.K.Hamirwasia
2	2	BSL Ltd (Process Division)	Shri A.K.Mehta
3	4	BSL Ltd	Shri J.C.Soni
4	10	Pratap Commercial Co.Pvt Ltd	Shri Hemant Mansinghka
5	11	Bhilwara Spinners Ltd.	Shri Ashok Kothari
6	14	RSWM Limited, Gulabpura	Shri Prakash Maheshwari
7	21	Udaipur Mineral Development Syndicate Pvt Ltd	Shri S.C.Panigrahi
8	22	A Infrastructurs Limited	Shri D. Ambardar
9	56	Shree Mahadeo Cotton Mills Ltd.	Shri Deepak Mansinghka
10	240	Sangam India Ltd.(Process Division)	Shri V.K.Sodani
11	245	Swastika Suitings Pvt Ltd.	Shri S.N. Soni
12	304	Sangam India Ltd.	Shri G.C.Jain
13	313	Ranjan Suitings Pvt Ltd.	Dr. P.M.Beswal
14	379	TPL Industries Ltd.	Shri V.S.Tiwari
15	393	Oswal Suitings Ltd.	Shri Sanjay Jain
16	394	J.K.Cement Works	Shri S.K.Rathore
17	427	Solar Synthetics Pvt Ltd.	Shri K.C.Nuwal
18	428	Anant Syntex Ltd.	Shri Anil Soni
19	432	Janki Corp Limited	Shri R.N.Mittal
20	433	Ranjan Processors	Shri Mohit Bhimsariya
21	932	Rodas Impex Pvt Ltd	Shri J.K.Chamodi
22	933	Airspun Synthetics Pvt Ltd	Shri Mukesh M Shah
23	934	Sona Styles Limited	Shri Subhash Nuwal
24	935	Subh Laxmi Tex Trade Pvt Ltd	Shri Amit Jain
25	936	Siddarth Export	Shri Manoj Mansinghka

Sr.	F.N.	Members Name	Representative
26	938	Di Shimla Sizers Pvt Ltd	Shri Dinesh Garg
27	939	Riddhi Siddhi Ecologistics Pvt Ltd	Shri Suresh Kumar Sharma
28	940	Baheti Silicones & Metals Pvt Ltd	Shri Sanjay Baheti
29	941	Kakani Yarn Agency	Shri Mahendra Kakani
30	944	Gravin (India)	Shri Rajendra Dhabriya
31	945	Arpit Enterprises	Shri Manoj Jain
32	946	Welcos Superfab	Shri Naresh Jain
33	948	Shivam Exim	Shri Chandresh Asawa
34	949	Saroj Textiles	Shri Vishesh Nuwal
35	950	Somani Chemical Industries	Shri Vinod Kumar Somani
36	951	Vinu Chemical & Allied Industries	Smt. Uma Somani
37	952	Somani Venture Private Limited	Shri Vinod Kumar Somani
38	953	Shree Nath Packing Industries	Shri Satya Narayan Jhanwar
39	954	BM Techno Machines Pvt Ltd	Shri Sandeep Maheshwari
40	955	Wearit Global Limited	Shri Manish Kumar

चुनाव अधिकारी के अनुसार, संविधान के अनुसार 10 सदस्य एसोसियट श्रेणी से चुनाव होकर आते है। इस श्रेणी में 10 नामांकन पत्र प्राप्त हुए एवं कोई नांमाकन पत्र वापस नही लिये जाने से निम्नानुसार 10 एसोसियट सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति में निर्विरोध चयनित हुये है।

Sr.	Constituency	Name of Unit	Name of the person
1	Textile Industry	Nitin Spinners Ltd.	Mr. Dinesh Nolkha
2	Minerals & Allied Industry	Hindustan Zinc Limited, Rampura	Mr. Praveen Jain
3	Cement, Building Materials, Iron & Steel, Chemicals Fertilizers, Refactories	Jindal Saw Limited	Mr. Rajender Gaur
4	Weaving Industry	Manglam Yarn Agencies	Mr. J.K.Bagrodia
5	Banking, Insurance & Service Providers	Bhilwara Mahila Urban Co-Op Bank Ltd	Dr.Kirti Bordia
6	Textile Processing Industry	M.R.Weaving Mills Pvt Ltd	Mr. D.K.Agarwal
7	Textile Machinery, Accessories, Dyes & Chemicals	Dr.Ashok Singal	Dr. Ashok Singal
8	General Industry	J.K.Tyre & Industries Ltd.	Mr. L.P.Shrivastva
9	Trade General	Jaya Agencies	Mr. M.S.Rathi
10	Yarn Trade, Agents and others	Sharda Spuntex Pvt Ltd	Mr. Anil Mansinghka

चुनाव अधिकारी ने बताया कि संविधान अनुसार 12 साधारण सदस्य प्रबंधकारिणी समिति में विभिन्न श्रेणियों से चुनाव द्वारा चयनित होते है। इस श्रेणी मे भी 12 नामांकन पत्र प्राप्त हुए एवं सभी 12 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए है, इन नाम निम्नानुसार है :–

Sr.	Constituency	Name of Unit	Name of the person
1	Transportation, Logistics, Automobile, Motor Spirit & Machinery	Shree Goods Carriers	Mr. Sanmati Jain
2	Marble, Granite & Tiles	Jindal Marbles Pvt Ltd.	Mr. N.N.Jindal
3	Metals, Engineering & Electricals	Talesara Electric Stores	Mr. P.S.Talesara
4	General	SR Texfab Private Limited	Mr. R.P.Agarwal
5	Electronics & Computers	Super Electronics	Mr. Mukesh Agarwal
6	Cottage, Small & Medium Scale Industries (MSME)	Modtex Texturisers Pvt Ltd.	Mr. K.K.Modi
7	Agriculture, Allied Trade, Oil Vanaspati & Readymade	Nathany Farm	Mr. S.P.Nathany
8	Professionals	Vinod Kumar Mansingka	Mr. V.K.Mansingka
9	General Trade	Furniture House	Mr. Ram Gopal Agarwal
10	Chartered Accountant	A.K.Somani & Associates	Mr. Atul Somani
11	Cinema, Hospitals & Service Providers	Excellent Synthetics	Mr. S.L.Pokharna
12	Advocates & Tax Practitioners	R.S.Jaithlia	Mr. R.S.Jaithalia

चुनाव अधिकारी ने बताया कि संविधान अनुसार 4 सदस्य एसोसियेशन श्रेणी से चुनाव होकर आते है। इस श्रेणी में 4 नामांकन पत्र प्राप्त हुए एवं इस श्रेणी से निम्न 4 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए है।

Sr.	Name of the Association	Name of Representative
1	Bhilwara Textile Agent Association	Mr. K.C.Prahladka
2	Bhilwara Branch of NIRC of ICSI	Mr. R.K.Jain
3	RIICO Growth Center Udyog Sanstha	Mr. J.P.Gadiya
4	Synthetics Weaving Mills Association	Mr. Sanjay Periwal

उपस्थित सभी सदस्यों ने हर्ष ध्वनि के साथ नवनिर्वाचित कार्यकारणी सदस्यों का अभिनन्दन किया। श्री एस पी नाथानी ने नामांकन पत्र जॉच अधिकारी श्री ए के दुग्गड के प्रति धन्यवाद् प्रस्ताव रखा। जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया।

तत्पश्चात् श्री अनिल मानसिंहका ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने पिछले वर्ष के कार्यकाल के दौरान मेवाड चेम्बर द्वारा निष्पादित मुख्य कार्यो की विवेचना करते हुए विशेषरुप से टफ योजना को चालू रखने एवं वित्तीय प्रावधानों के लिए मेवाड चेम्बर के प्रयासों एवं प्रतिनिधिमण्डल के रुप में केन्द्र में वित्तराज्य मंत्री, वित्त सचिव, कपडा मंत्री आदि से मुलाकात के बारे में बताते हुए कहाकि इस योजना को चालू रखवाने में पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे संगठन का रहा है। उन्होंने मिलान चेम्बर एवं इण्डो–पोलिस चेम्बर के साथ निष्पादित एमओयू के बारे में बताते हुए कहाकि यद्यपि स्थानीय उद्योगों ने इनका बहुत अधिक फायदा नही उठाया लेकिन पॉलेण्ड एवं इटली के विभिन्न उद्योग एवं व्यापारिक संगठनों ने मेवाड चेम्बर से सम्पर्क कर, भारत से अपने व्यापार को कई गुणा बढाने का कार्य किया है। श्री मानसिंहका ने सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने पदाधिकारियों, कार्यकारणी सदस्यों एवं अन्य सदस्यों के सहयोग के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

अन्य सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करने पर पूर्वाध्यक्ष डॉ पी एम बेसवाल ने सुझाव दिया कि कार्यकारणी समिति में जो 20 सदस्य एसोसियेट श्रेणी से बाई–रोटेशन आते है, वह एकदम नये बल्कि चालू वर्ष में बने सदस्य ही होते है। ऐसे सदस्यों को चेम्बर के क्रियाकलापों का अनुभव भी नही होता है एवं प्रायः उनकी उपस्थिति भी नही होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बाई–रोटेशन में कम से कम 5 वर्ष के अनुभवी सदस्यों को लिया जाना चाहिए एवं इसके लिए नया सिस्टम बनाया जाना चाहिए। कई सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर मंथन कर कार्यकारणी समिति में रखा जाकर, आवश्यकता होने पर अगली आमसभा में (संविधान संशोधन हेतु) रखा जाए।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(सूर्य प्रकाश नाथानी)
मानद महासचिव

आमसभा 20.02.2016 को उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नानुसार है –

1	श्री अनिल मानसिंहका	शारदा स्पनटेक्स प्रा लि
2	श्री जे सी लढ्ढा	सुदिवा स्पिनर्स प्रा लि
3	डॉ पी एम बेसवाल	रंजन सुटिंग प्रा लि
4	श्री एस पी नाथानी	नाथानी फार्म
5	श्री दिनेश नौलखा	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड
6	श्री जे के बागडोदिया	मंगलम यार्न
7	श्री आर के जैन	भीलवाडा चेप्टर ऑफ आईसीएसआई
8	श्री ए के सोमाणी	ए के सोमाणी एण्ड एसोसियेट
9	श्री एस एल पोखरना	राजस्थान कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन
10	श्री पी एस तलेसरा	तलेसरा इलेक्ट्रीक स्टोर
11	श्री के के मोदी	मोडटेक्स टेक्सटराइजर्स प्रा लि
12	श्री राजेन्द्र गौड	जिन्दल शॉ लिमिटेड
13	श्री जे पी गदिया	रीको ग्रोथ सेन्टर उद्योग संस्था
14	श्री आर एस अग्रवाल	भीलवाडा ऑटोमोबाइल मशीनरी डीलर एसोसियेशन
15	श्री कैलाश प्रहलादका	भीलवाडा टेक्सटाइल एजेन्ट एसोसियेशन

16	श्री पवन गुप्ता	आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड गुलाबपुरा
17	श्री मुकेश अग्रवाल	सुपर इलेक्ट्रोनिक्स
18	श्री सन्मती जैन	श्री गुड्स केरियर
19	श्री एस आर जैन	श्री केरियर्स प्रा लि
20	श्री डी अम्बरदार	ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
21	श्री एस के गोयल	मृदुल मैन्यौर मिल्स प्रा लि
22	श्री गोपाल बल्दवा	बल्दवा सिन्थेटिक्स प्रा लि
23	श्री एम एस राठी	जया एजेन्सीज
24	डॉ अशोक सिंघल	
25	श्री वी के मानसिंगका	
26	श्री आर एस जैथलिया	
27	श्री बी एस नन्दवाना	

आमसभा 20.02.2016 को निम्न सदस्यों ने अवकाश के लिए प्रार्थना की, जिसे मंजूर किया गया –

1	श्री आर पी सोनी	पूर्वाध्यक्ष
2	श्री एस एन मोदानी	पूर्वाध्यक्ष
3	श्री वी के सोडानी	संगम इण्डिया लिमिटेड (प्रोसेस डिविजन)
4	श्री जी सी जैन	संगम इण्डिया लिमिटेड (स्पिनिंग डिविजन)
5	श्री प्रवीण जैन	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, रामपुरा आगुचा
6	श्री प्रकाश माहेश्वरी	आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड गुलाबपुरा
7	श्री वी के हमीरवासिया	बिडला कॉरपोरेशन लिमिटेड
8	श्री ए के मेहता	बीएसएल लिमिटेड (प्रोसेस डिविजन)
9	श्रीमति कीर्ति बोरदिया	भीलवाडा महिला अरबन कॉपरेटीव बैंक लि
10	श्री वी एस तिवाडी	टीपीएल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
11	श्री एल पी श्रीवास्तव	जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. कांकरोली
12	श्री दीपक अग्रवाल	एम आर विविंग मिल्स लिमिटेड
13	श्री एन एन जिन्दल	जिन्दल मार्बल प्रा लि
14	श्री आर पी अग्रवाल	एस आर टेक्सफेब प्रा लि

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भीलवाडा
कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2016

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की वार्षिक आमसभा दिनांक 20.02.2016 को मेवाड़ चेम्बर भवन में आयोजित की गई। तत्पश्चात् नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वाध्यक्ष श्री जे सी लढ्ढा ने की।

पदाधिकारी चुनाव

बैठक में श्री एस पी नाथानी ने सुझाव रखा कि चुंकि परम्परा अनुसार वर्ष 2015 के पदाधिकारियों को एक वर्ष ओर रखा जाना है अतः एक–एक पदाधिकारी के चुनाव के बजाय पूरी टीम को ही वर्ष 2016 के लिए चयनित कर लिया जाए। इस पर सभी अपनी सहमति प्रदान की एवं सर्वसम्मति से निम्न पदाधिकारी वर्ष 2016 के लिए चयनित घोषित किये गये।

पद	नाम
अध्यक्ष	श्री अनिल मानसिंहका
वरिष्ठ उपाध्यक्ष	श्री दिनेश नौलखा
उपाध्यक्ष – प्रथम	श्री एन एन जिन्दल
उपाध्यक्ष – द्वितीय	श्री जे के बागडोदिया
उपाध्यक्ष – तृतीय	श्री प्रवीण जैन
मानद महासचिव	श्री सूर्य प्रकाश नाथानी
मानद सयुक्त सचिव	श्री आर के जैन
मानद कोषाध्यक्ष	श्री दीपक अग्रवाल

पुर्ननिर्वाचित अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका ने अपने उद्‌बोधन में इस वर्ष के दौरान चेम्बर के 50 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष में मनाये जाने वाले गोल्डन जुबली समारोह के विषय में बताया एवं पूर्व में कार्यकारणी में हुई चर्चा के अनुसार इस कार्यक्रम को भव्य रुप में मनाने एवं उसके लिए प्रारम्भिक तैयारियों की जानकारी देते हुए सभी सदस्यों से चेम्बर की परम्परा एवं गरिमा अनुरुप पूर्ण सक्रिय रुप से कार्य करने का एवं पूर्वतः सक्रिय योगदान का अनुरोध किया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(सूर्य प्रकाश नाथानी)
मानद महासचिव

कार्यकारणी समिति की दिनांक 20.02.2016 को उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नानुसार है –

1	श्री अनिल मानसिंहका	शारदा स्पनटेक्स प्रा लि
2	डॉ पी एम बेसवाल	रंजन सुटिंग प्रा लि
3	श्री एस पी नाथानी	नाथानी फार्म
4	श्री दिनेश नौलखा	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड
5	श्री जे के बागडोदिया	मंगलम यार्न
6	श्री आर के जैन	भीलवाडा चेप्टर ऑफ आईसीएसआई
7	श्री ए के सोमाणी	ए के सोमाणी एण्ड एसोसियेट
8	श्री एस एल पोखरना	राजस्थान कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन
9	श्री पी एस तलेसरा	तलेसरा इलेक्ट्रीक स्टोर
10	श्री के के मोदी	मोडटेक्स टेक्सटराइजर्स प्रा लि
11	श्री राजेन्द्र गौड	जिन्दल शॉ लिमिटेड
12	श्री जे पी गदिया	रीको ग्रोथ सेन्टर उद्योग संस्था
13	श्री कैलाश प्रहलादका	भीलवाडा टेक्सटाइल एजेन्ट एसोसियेशन
14	श्री प्रकाश माहेश्वरी (श्री पवन गुप्ता)	आरएसड्‌ब्ल्यूएम लिमिटेड गुलाबपुरा
15	श्री मुकेश अग्रवाल	सुपर इलेक्ट्रोनिक्स
16	श्री सन्मती जैन	श्री गुड्‌स केरियर
17	श्री डी अम्बरदार	ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
18	श्री एम एस राठी	जया एजेन्सीज
19	डॉ अशोक सिंघल	
20	श्री वी के मानसिंगका	
21	श्री आर एस जैथलिया	

कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2016 को निम्न सदस्यों ने अवकाश के लिए प्रार्थना की, जिसे मंजूर किया गया –

1	श्री वी के सोडानी	संगम इण्डिया लिमिटेड (प्रोसेस डिविजन)
2	श्री जी सी जैन	संगम इण्डिया लिमिटेड (स्पिनिंग डिविजन)
3	श्री प्रवीण जैन	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, रामपुरा आगुचा
4	श्री वी के हमीरवासिया	बिडला कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	श्री ए के मेहता	बीएसएल लिमिटेड (प्रोसेस डिविजन)
6	श्रीमति कीर्ति बोरदिया	भीलवाडा महिला अरबन कॉपरेटीव बैंक लि
7	श्री वी एस तिवाडी	टीपीएल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
8	श्री एल पी श्रीवास्तव	जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. कांकरोली
9	श्री दीपक अग्रवाल	एम आर विविंग मिल्स लिमिटेड
10	श्री एन एन जिन्दल	जिन्दल मार्बल प्रा लि
11	श्री आर पी अग्रवाल	एस आर टेक्सफेब प्रा लि

MUKHYAMANTRI JAL SWAVLAMBAN ABHIYAN

Thousands have lived without love, not one without water." Poet W.H. Auden beautifully captures the essence of water for life in these few words. In a startling study of statistics, it is estimated that only 18% of total rural population of 833 million Indians have access to treated water. In comparison, 41% of the rural population, or 346 million people, own mobile phones. The situation is worse in the only desert state of the India, Rajasthan. Consisting of approximately 10% of land area, 5% of the total population, the State has only 1% water of the Country. A 2012 report of Rajasthan State Action Plan on Climate Change reveals that Rajasthan has the highest probability of drought in India. The State of Rajasthan, under CM Vasundhara Raje, has earmarked 2016 as the 'Year of JalKranti'.

All about MJSA

With a vision to find long-term solution for a water-sustainable Rajasthan, CM Vasundhara Raje has recently announced her most ambitious scheme "Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan (MJSA) to conserve and harvest rain water and make villages self-reliant even during drought periods. The programme has been designed in such a way that everything from planning to execution shall be followed in a participatory approach down to the village community level. The scheme is created with the idea of natural resource management with hydrological unit as a base to develop water, forest and land. The purpose of this Mission on Water Conservation is to make villages self-sufficient in water use and thus provide a permanent solution to the demand of drinking water besides ensuring storage and conservation of water for making it available for irrigation. In first year around 3000 villages on the basis of priority will be identified and, in coming 3 years, by including around 6000 villages every year, 21000 villages of the State will be benefited by the mission & permanent solution will be achieved by making them self sufficient in terms of water.

Some of the key objectives of the programme are:

- To create a water sustainable Rajasthan
- To increase the irrigated area Ensure effective water conservation through convergence of resources of different departments
- To create awareness about community participation in water management
- To prepare a village action plan through water budgeting via community participation
- To make the village a self sufficient unit in drinking water through sustainable measures

Four Waters Concept

Four waters concept, which has been successful in countering drought and averting migration of labour in China, is quite relevant to the drought-prone Rajasthan. This low-cost technology can increase recharge of groundwater by four times and provide thrice the benefit than conventional modes. The Four Waters concept revolves around the harvesting of available runoff (rain water, ground water, under-ground water & in situ soil moisture) in rural areas by treatment of catchment, proper utilization of available water harvesting structures, renovation of the non-functional water harvesting structures & creation of new water harvesting structures. It also includes development of forest, land, water & fauna keeping watershed/cluster/index as a unit for natural resource management.

Water Budgeting

To ensure effective implementation of water conservation and water harvesting related activities in rural areas, convergence of schemes of various departments has been carried out. The planning also involves ensuring people's participation through both education and motivation at the village level. A unique concept of water budgeting is being introduced in Gram sabhas where after determination of usage of water (for drinking, irrigation, livestock & for other commercial purposes) & a water budget will be prepared to conserve water available from various resources and accordingly, works will be identified and approved for the preparation of action plan of the mission.

Water for all – by all

The root of the campaign lies in the premise that problem can be solved at its source if rural indigenous communities are mobilized to produce water — that is, to increase the supply of water available for their own needs and, by extension, for society as a whole. Increasing society's ability to produce water, as well as use it more efficiently, can bring about an interrelated series of benefits that will dramatically improve environmental, sanitary, and productive conditions among some of the poorest social groups. It involves a bottom-up approach of involving the primary stakeholders in planning, designing, developing and management of water conservation activities. Overall, primary efforts are being made to create a sense of ownership among villagers for construction of water harvesting/conservation structures and their maintenance.

Crowd-Funding

For the Rajasthan Government, the problem looks gigantic and resources are scarce. Probably for the first time ever, the Rajasthan Government has created an online crowd-funding portal where donations for the campaign shall be accepted to a single rupee. The portal consists of a unique feature through which one can adopt a village or a lake in Rajasthan and contribute for the same. With planning in initial stages, there is a discussion of making contributions enabled through e-mitras and web payment gateways.

CM Raje has set out on a mission mode, calling on all stakeholders across the State to contribute to the campaign – the government departments, Non-Government Organizations, civil society, religious institutions and leaders from all political parties. The Government is also set to invite Businesses to contribute towards MJSA through a CSR sub-campaign. Another sub-campaign called 'Chalo Rajasthan' will be soon launched to call on the non-resident Rajasthanis to contribute to the mission. CM Vasundhara Raje has appealed to all the people of Rajasthan to step in, join hands and work together for the cause of this Jal Kranti.

In the spirit of 'charity begins at home', Chief Minister Raje herself announced to contribute her salary of six months to support the Jal Swavlamban Abhiyan. On her call, people representatives and all ministers and mayors announced a donation of 3 months' salary along with zila pramukhs donating their two months' salaries. MPs, MLAs and board Chairpersons also pledged their one-month salary to the cause.

How can You contribute

Any citizen can donate any amount through this portal: http://water.rajasthan.gov.in/mjsa Corporate Sector, Non-Governmental Organizations & Religious Trusts have full freedom to execute plan of any particular village as a whole or a particular work of village plan, by themselves as per guidelines. May adopt any village as a whole or works of a particular village and can execute works themselves under technical guidance of Line Department.

In addition to above, may contribute funds to bridge Financial Gaps for works proposed in village plan.

While the world's rising requirement for water is a big threat for the future, the story is more complicated than just too many people putting their straws in the glass. The growing conflicts over water use are worrying and it seems that human race has taken water for granted and massively misjudged the capacity of the earth's water systems to sustain the demands made upon it. In crisp white letter, water conservation ought to be, and must be, the foremost agenda for any government. Water is known to take many forms; we must not force it to take a fatal one. In hindsight, this bold move of Vasundhara Raje is greatly warming and welcome.

राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2014–15

राजस्थान सरकार की ओर से उत्कृष्ट निर्यात हेतु वर्ष 2014–15 के लिए राजस्थान निर्यात पुरस्कार के आवेदन आंमत्रित किए गए है। मेवाड चेम्बर की ओर से सभी निर्यातकों को मेल से सूचित किया गया है। आवेदन पत्र दिनांक 7 अप्रेल 2016 तक जिला उद्योग केन्द्र के मार्फत भिजवाये जा सकते है। आवेदन पत्र के प्रारुप उद्योग विभाग की वेबसाइट http://industries.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

रिसर्जेंट राजस्थान में हुए एमओयू पर वित्त विभाग की स्वीकृति

रिसर्जेंट राजस्थान में हुए एमओयू को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढाये है। एमओयू हुए प्रोजेक्ट को अतिरिक्त लाभ देने के लिए सरकार ने राजस्थान की आठ और कंपनियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इनमें दो भीलवाड़ा की भी शामिल हैं। ये कंपनियां मैसर्स सुपर गोल्ड सूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मंडपिया और मैसर्स आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड कान्याखेड़ी हैं।

वित्त विभाग (टैक्स डिविजन) की ओर से एक फरवरी को जारी आदेश के अनुसार दोनों कंपनियों के एमओयू रिसर्जेंट राजस्थान में होने से उन्हें एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी सहित पैकेज की अन्य सुविधाएं दी जाएगी। आरएसडब्ल्यूएम कंपनी 179 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इससे करीब 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी कॉटन यार्न बनाने पर निवेश करेगी। सुपर गोल्ड कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें करीब 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी डेनिम फेब्रिक बनाएगी।

सोमानी एक्सल विट्रीफाइड प्रा.लि. भीलवाडा में अपनी इकाई स्थापित कर 115 करोड़ रूपये का निवेश करेगी जिसमें 150 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 125 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कम्पनी धीरे–धीरे 500 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। इसी प्रकार कंचन इण्डिया लि. भीलवाड़ा के मन्द की बावड़ी तथा नानकपुरा में स्थापित अपने प्लांट का 300 करोड़ रूपये का निवेश कर विस्तार करेगी। इससे 935 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

UNION BUDGET 2016-2017

Budget 2016-17 Highlights

1. Service tax - After Swachh Bharat Cess, Govt goes for Krishi Kalyan Cess of 0.5% on all taxable services from June 1, 2016 but Credit to be allowed against CESS payments
2. 1% infrastructure cess on small petrol & diesel cars + CNG cars & 4% on higher engine capacity vehicles; No Credit to be allowed even against CESS payments
3. Clean Energy Cess hiked to Rs 400 per tonne on coal, lignite and peat
4. FM proposes equalisation levy of 6% on payments exceeding Rs one lakh and made to non-resident in case of B2B transactions
5. STT hiked in case of 'Options'
6. 1% corporate tax relief for Companies with turnover not exceeding Rs 5 Crore by 2015
7. Budget hikes tax rebate u/s 87A from Rs 2000 to Rs 5000 for taxpayers with income upto Rs 5 lakh
8. FDI policy - 100% FDI through FIPB route in food processing
9. Budget promises abolition of permit raj for pax transport traffic + to amend Motor Vehicle Act + 160 airports & airstrips to be revamped
10. Govt announcements on infra sector - special system to resolve contract-related disputes
11. Budget 2016 - Govt committed to double income of farmers by 2020 + more funds for agriculture & rural sector
12. FM announces 9% interest on refund in case of delay in giving effect to decisions given by appellate forum
13. Budget proposes to streamline TDS provisions + relief for non-resident not having PAN + introduces system of deferral scheme for payment of customs duty
14. CESTAT Single Member Bench - Limit hiked to Rs 50 lakh + 11 more Benches for CESTAT + CENVAT Credit Rules streamlined + accepts some of recommendations of Justice Easwar Committee
15. FM announces new scheme to reduce tax litigation by paying 15% of demand
16. FM proposes to rationalise formula to overcome issues relating to Sec 14A
17. Retro tax cases - High Level Committee headed by Revenue Secretary to decide new cases + one-time dispute resolution scheme proposed for cases pending in courts + proposes to reduce powers of AOs to impose penalty
18. Tax Litigation - 3 lakh cases involving Rs 5.5 lakh crore - Scheme proposed not to levy penalty upto Rs 10 lakh for direct & indirect taxes; 20% of minimum assessed sum and penalty also proposed
19. Anti-black money drive - FM announces 'Compliance Window' for domestic black money at 45% tax rate
20. Excise duty on tobacco products except bidis hiked by 10-15%
21. FM announces Infrastructure Cess in name of congestion on roads
22. FM proposes withholding tax for e-commerce entities having no PE but earning ad revenue in India
23. Rich to pay 10% more tax on dividend exceeding Rs 10 lakhs
24. To revive housing sector FM announces 100% deduction for projects in metros and other cities + proposes deduction of addl sum of Rs 50000/- for interest payment
25. FM extends list of negative services
26. New tax regime for ARCs + 5% deduction for bad loans of NBFCs + GAAR further postponed by one year + BEPS project - certain measures like country by country reporting taken
27. Corporate tax regime reform - Accelerated depreciation limited to 40% + Sec 10AA benefit to continue till 2020 + New tax regime for New manufacturing Cos + 100% deduction for Startups for 3 out of five years + no capital gains for startups
28. FM hikes Sec 80GG limit from Rs 24K to 60K + presumptive taxation - turnover limit hiked to Rs 2 Cr for small businesses + extends presumptive taxation to professionals having Rs 50 lakh receipt
29. FM makes provision of funds for implementation of recommendations of 7th Pay Commission
30. Govt to set up Committee to review implementation of FRBM Act
31. FM announces no more distinction of non-plan and plan expenditure from 2017
32. FM decides to stick to fiscal targets; 3.5% for 2016-17; Total expenditure to be Rs 19.78 lakh crore with Rs 5.5 lakh Plan expenditure
33. Budget announces public sector insurance Cos to be listed in stock exchanges
34. FM announces Rs 25000 Cr fund for capitalisation of public sector banks

35. FDI policy - 100% FDI through FIPB route in food processing
36. Govt announcements on infra sector - special system to resolve contract-related disputes
37. Budget promises abolition of permit raj for pax transport traffic + to amend Motor Vehicle Act + 160 airports & airstrips to be revamped
38. FM announces 97000 Cr public investment in roads in next fiscal
39. Budget extends coverage of Section 80JJAA to all audited companies, including in Services Sector
40. FM announces more Navodaya Vidyalaya + to set up higher education financing agencies + to set up
41. Budget on social sectors - LPG connections for BPL families + Rs 38500 Cr for MNREGA + to provide dialysis service in district health centres and medical equipment granted customs duty exemption
42. FM announces digital literacy scheme for rural India + to introduce digitalisation of land records management system
43. Budget allocates Rs 5000 Cr for crop insurance scheme
44. Govt to spend Rs 60,000 Cr on water management system
45. FM allocates Rs 17000 Cr for irrigation + Rs 19000 Cr for PM Gram Sadak Yojana with 40% contribution by States Budget 2016 - Govt committed to double income of farmers by 2020 + more funds for agriculture & rural sector.

Contributed By Shri Anil Mishra,
J.K.Tyre & Industries Ltd, Kankroli

NOTIFICATIONS WHICH ARE APPLICABLE ON TEXTILES UNDER BUDGET 2016-17

Excise notification have made following modifications under various notifications issued on 01.03.2016. Govt. has proposed to change the excise duty on branded readymade garments and made up articles of textiles with a retail sale price of Rs.1,000 and above from 'Nil without input tax credit or 6%/12.5% with input tax credit' to '2% without input tax credit or 12.5% with input tax credit'.

- Under notification no 7/2016-Central Excise amendments in in the principal notification no 7/2012-Central excise dates the 17th march 2012 where in “all goods of cotton not containing any other textile material, other than those bearing a brand name or sold under a brand name and having retail sale price of Rs. 1000 and above”
- Under notification no 9/2016-Central Excise amendments in in the principal notification no 1/2011-Central excise dates the 1st march 2011 where in “all goods of Chapter 61, 62, 63 (except laminated jute bags falling under 6305, 63090000, 6310) bearing a brand name or sold under a brand name and having retail sale price of Rs. 1000 and above”

Customs notification have made following modifications under Notification issued on 01.03.2016.

- Under notification no 12/2016-Customs 1st march 2016 govt. has proposed to add following items in the said notification 12/2012-Customs dated 17th March 2012 in the table with amended custom duty as stated in columns 4

1	2	3	4	5	6
	50, 52, 54, 55 or any other chapter	Cotton and Elastane blended printed fabrics	Nil	-	28 A",
		Cotton and metallic yarn dyed blended fabrics			
		Cotton and spandex and metallic blended fabrics			
		Cotton and Elastane printed fabric			
		Cotton and silk lining fabric			
		Cotton and silk lining fabric 100% linen chambray woven/dyed fabric			
		100% ramie dyed /blended printed yarn dyed fabric			
		Nylon and spandex lining fabrics			
		100% polyester velvet dyed fabric			
		Cotton / Nylon / Embroidery crochet lace lining fabric			
"290A	5402 19 90	Nylon 66 filament	2.5%	-	-
	5402 52 00	Polyester yarn-Anti Static Filament			
	5503 11 00	Aramid Flame Retardant Fibre			
	5503 11 00	Para- aramid Fibre			
	5503 19 00	Nylon Staple Fibre			
	5503 19 00	Nylon Anti Static Staple fibre			
	5503 30 00	Modacrylic fibre			
	5504 10 00	Flame Retardant Viscose Rayon Fibre			

बजट सम्बन्धित प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी कुछ प्रेसनोट

छोटे करदाताओं और अन्य के लिए कर में कुछ राहत की घोषणा

लोकसभा में आज आम बजट 2016–2017 प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के पास गरीबी और असमानता दूर करने के लिए कराधान प्रमुख साधन है और इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा, लेकिन वे छोटे करदाताओं को राहत देना चाहते हैं।

इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 87 ए के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे दो करोड़ से अधिक करदाताओं को 3000 रुपये की राहत मिलेगी। धारा 80 जीजी के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी।

आयकर अधिनियम की धारा 44 एडी के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना के तहत टर्नओवर या सकल प्राप्तियों को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई है, जिसका लाभ लगभग 33 लाख छोटे व्यवसायियों को मिलेगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को विस्तृत बही खातों के रख–रखाव और उनकी लेखा परीक्षा कराने के बोझ से मुक्ति मिलेगी।

अनुमानित कराधान योजना को ऐसे व्यवसायियों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी अनुमानित 50 प्रतिशत की प्राप्तियों के साथ सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपये की हैं।

राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा, 2016–17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3000 स्टोर खोले जाएंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2016–2017 का आम बजट पेश करते हुए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की है। संसद में अपनी बजट घोषणा में वित्त मंत्री ने चिंता जताई कि परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीबों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालती है। ऐसे परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करेगी जो प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती रही है। उन्होंने कहा कि हम जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में फिर से तेजी लाएंगे और 2016–2017 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3000 स्टोर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने एक राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए राशि पीपीपी मॉडल के जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराई जा सके।

अनुपालन विंडो में 45 प्रतिशत कर का भुगतान कर अघोषित आय घोषित करने की योजना के जरिए कालाधन कम करना

लोकसभा में आज आम बजट 2016–2017 प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि अनुपालन विंडो में 45 प्रतिशत कर का भुगतान कर अघोषित आय घोषित करने की योजना का प्रस्ताव रखा।

श्री जेटली ने अघोषित आय या परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत आय घोषित करने के लिए घरेलू करदाताओं हेतु सीमित अवधि अनुपालन विंडो का प्रस्ताव किया। इसमें 30 प्रतिशत की दर से कर और 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा 7.5 प्रतिशत की दर से दंड शामिल है, जो अघोषित आय का कुल 45 प्रतिशत होता है। आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति कर अधिनियम के तहत इन विवरणों में घोषित आय के संबंध में कोई छान–बीन या जांच नहीं होगी और घोषणा करने वाला अभियोजन से मुक्त होगा। शर्तों के अधीन बेनामी लेन–देन (निषेध) अधिनियम 1988 से भी छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

अघोषित आय का 7.5 प्रतिशत की दर पर लगाए गए अधिभार को ''कृषि कल्याण अधिभार'' कहा जाएगा, जिसका कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा। भारत सरकार की 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक चलने वाली इस आय खुलासा योजना के तहत, घोषणा के दो महीने के अंदर देय राशि अदा करने के विकल्प के साथ नई विंडो खोलने की योजना है।

श्री जेटली ने भारत सरकार की अर्थव्यवस्था से कालाधन हटाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार छिपाई गई आय घोषित करने का अवसर देने के बाद वे कालाधन वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए समस्त संसाधन लगा देंगे।

रेलवे के पूंजीगत व्यय को मिलाकर सड़कों और रेलवे के लिए कुल 218000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया

बजटीय अनुमान 2016–17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्यय 221246 करोड

लोकसभा में आज आम बजट 2016–17 प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि बुनियादी ढांचा और निवेश बजट

विषय ''ट्रांसफॉर्म इंडिया'' का पांचवां सहायक स्तंभ है। 2016–17 में सड़क और रेलवे के परिव्यय पर कुल 218000 करोड़ रुपये का व्यय होगा। सड़क निर्माण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 27000 करोड़ रुपये के आबंटन और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग के लिए 55000 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। अन्य 15000 करोड़ रुपये बॉन्ड के जरिए एनएचएआई द्वारा लगाए जाएंगे। रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए 121000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

श्री जेटली ने घोषणा की कि 2016–17 में तकरीबन 10000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त करीब 50000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। बजटीय अनुमान 2016–17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल 221246 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी और यात्री सड़क–परिवहन क्षेत्रों को यात्री खंड में खोलेगी। राज्यों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उन्हें नए विधिक ढांचे को अपनाने का विकल्प दिया जाएगा। उद्यमी कार्यदक्षता और सुरक्षा मानदंडों का पालन कर विभिन्न मार्गों पर बसें चला सकेंगे। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होगा तथा नए निवेश, रोजगार पैदा करने तथा स्टार्ट–अप उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तमंत्री ने कहा, हम देश के पूर्वी और पश्चिमी तट में नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग के कार्य में तेजी लाई जा रही है और इस पहल के लिए 800 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा असेवित और अल्पसेवित विमानपत्तनों को दोबारा चालू किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी भी की जा रही है।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी स्थापित करने का फैसला।

विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के तौर पर उभरने के लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्थाओं को समर्थ बनाया जाएगा, शेष जिलों में अगले 2 वर्षों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

सरकार ने अगले दो वर्षों में शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016–17 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत बड़ा आवंटन किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के तौर पर उभरने में सहायता देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना सरकार की वचनबद्धता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना उपलब्ध करायी जाएगी।

अपने बजट भाषण में श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) स्थापित करने का फैसला किया है।

रेल बजट 2016–2017

इस वर्ष के रेल बजट में यात्री भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है। रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को संसद में वर्ष 2016–2017 का रेल बजट पेश करते हुए रेलवे की उपलब्धियों, योजनाओं के निष्पादन और आगामी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी दी। श्री प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अभिकल्पना और नेतृत्व ने भारतीय रेल को बेहद प्रोत्साहन दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति और आर्थिक विकास की रीढ़ बनाना ही उनका दृढ़ इच्छा है। रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 2020 तक आम आदमी की लंबे समय से चली आ रही आशाओं को पूर्ण करने की वचनबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक–निजी भागीदारी के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति भी मिल चुकी है।

श्री प्रभु ने रेलवे को और सुविधायुक्त बनाने के क्रम में, भारतीय रेल में यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया गया है। इनके तहत रेलों में 65000 अतिरिक्त बर्थ और 2500 वैंडिग मशीनें उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे ने विश्व का प्रथम बॉयो–वैक्यूम टॉयलेट विकसित किया है और रेलों में 17000 बॉयो–टॉयलेट प्रदान किए जाएगें। रेलों के परिचालन में सुधार लाने के लिए गाजियाबाद से मुगलसराय तक परिचालन ऑडिट प्रारंभ किया जाएगा। रेलवे में संपूर्ण देश में मोबाइल ऐप के साथ–साथ 1780 स्वाचालित टिकिट मशीने भी लाने का प्रस्ताव है। उन्होने कहा कि 400 और स्टेशनों पर वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।

श्री प्रभु ने कहा कि 2020 तक आम आदमी की लंबे समय से चली आ रही आशा को पूरा करने के अंतर्गत गाड़ियों में आरक्षित एकोमोडेशन मांग पर उपलब्ध होना, मालगाड़ियों का समय–सारणी के अनुसार चलना, संरक्षा रिकॉर्ड में सुधार लाने के लिए अत्याधुनिक टैक्नॉलोजी, बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त करना, उन्नत समय–पालन, माल गाड़ियों की उच्चतर औसत गति, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें जो स्वर्णिम चतुर्भुज पर चलें, मानव अपशिष्ट का जीरो डायरेक्ट डिस्चार्ज शामिल है।

रेल मंत्री ने कहा कि 2015–2016 के लिए 139 बजट उद्घोषणाओं पर कार्रवाई प्रारंभ की गई है। 2015–16 के लिए जीवन बीमा निगम के जरिए सुनिश्चित वित्तपोषण, 2500 किलोमीटर बड़ी आमान लाइनों को चालू करना; 1600 किलोमीटर का विद्युतीकरण चालू करना; 2016–17 में 2800 किलोमीटर रेलपथ को चालू करने का लक्ष्य निर्धारण; बड़ी आमान लाइनों पर पिछले 6 वर्षों में लगभग 4.3 किमी प्रति दिन की औसत की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति दिन की गति से चालू करने का लक्ष्य है। यह 2017–18 में लगभग 13 किलोमीटर प्रतिदिन और 2018–19 में 16 किलोमीटर प्रतिदिन तक बढ़ जाएगा। 2017–18 में लगभग 9 करोड़ श्रम दिवस के रोजगार सृजन; 2016–17 में रेलवे विद्युतीकरण के लिए परिव्यय लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसे 2000 किलोमीटर तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

रेलमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2016 तक लोक अभियांत्रिकी निर्माण कार्यों के लिए लगभग सभी ठेके दिए जाने है। पिछले 6 वर्षों में दिए गए 13000 करोड़ रुपये के ठेकों की तुलना में नवंबर 2017 से 24000 करोड़ रूपये के ठेके आबंटित किए गए हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित नवीन वित्तपोषण के जरिए उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम और पूर्व तट माल गलियारों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि टूना बंदरगाह शुरू कर दिया गया है और जयगढ़, दीघी, रेवास और पारादीप पोर्ट के लिए रेल संपर्क की परियोजनाओं का कार्यन्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नारगोल और हाजिरा पोर्ट के लिए रेल कनेक्टिविटी का कार्यन्वयन। असम में बड़ी लाइन पर लमडिंग–सिलचर खंड खोल दिया गया है और इससे बराक घाटी देश के साथ जुड़ गई है; अगरतला भी बड़ी लाइन से जुड़ गया है। कटखल–भैराबी और अरुणाचल–जीरीबाम की ब्रॉड गेज परिवर्तन परियोजनाएं जल्द ही खोल दिए जाने पर मिजोरम और मणिपुर राज्य भी देश में बड़ी लाइन से जुड़ जाएंगे।

रेल मंत्री ने कहा कि उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल संपर्क परियोजना का कटरा–बनिहाल खंड का कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है; कुल 95 किलोमीटर में से, 35 किलोमीटर सुरंग का कार्य पूरा हो गया है; जालंधर–जम्मु लाइन में भीड़–भाड़ कम करने का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है और मार्च, 2016 तक दो पुलों का दोहरीकरण का कार्य पूरा कर उन्हें चालू कर दिया जाएगा, जबकि अन्य दो पुलों को 2016–17 तक पूरा कर लिया जाएगा।

रेल मंत्री ने कहा कि ग्राहक इंटरफेस के तहत सोशल मीडिया और समर्पित आईवीआरएस सिस्टम के माध्यम से संवाद और फीडबैक प्राप्त किया जाता है। यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए 65000 अतिरिक्त शायिकाएं बनाना, 2500 वाटर वेंडिंग मशीनें लगाना, आधुनिक साज–सज्जा के सवारी डिब्बों वाली महामना एक्सप्रेस चलाना, गाड़ियों में 17000 जैव–शौचालय की व्यजवस्था करना; विश्व का पहला बायो–वैक्यूम टॉयलेट विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि समयपालन में सुधार के लिए गाजियाबाद से मुगलसराय खण्ड के लिए परिचालन ऑडिट की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। टिकटिंग के अन्तर्गत 1780 ऑटोमेटिक टिकट वेण्डिंग मशीनें लगानाए यूटीएस एवं पीआरएस टिकटों की कैशलेस खरीद के लिए मोबाइल एप और गो इण्डिया स्मोर्ट कार्ड, ई–टिकटिंग सिस्टम की क्षमता को 2000 प्रति मिनट से बढ़ाकर 7200 टिकट प्रति मिनट करना और एक ही समय पर 120000 उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकते हैं जबकि पहले केवल 40000 ही कर सकते थे।

श्री प्रभु ने कहा कि सामाजिक पहल के तहत ऑनलाइन टिकट बुक करते समय रियायत पाने के लिए एक बारगी पंजीकरण, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयरों की ऑनलाइन बुकिंग और ब्रेल सुविधा से युक्त नए सवारी डिब्बों का प्रावधान करना; वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए निचली बर्थों का कोटा बढ़ाना; महिलाओं के लिए सवारी डिब्बों में मिडल बर्थ को आरक्षित करना शामिल है।

रेल मंत्री ने कहा कि रेल विश्वविद्यालय की मुहिम के तहत प्रारंभ में वड़ोदरा स्थित भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी की पहचान की गई है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ट्रैक प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) एप्लीकेशन शुरू की गई है।

रेल मंत्री ने बताया कि यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ–साथ **अनारक्षित यात्रियों के लिए** भी निम्न कदम उठाए जाने है–

- ❑ अंत्योदय एक्सप्रेस अनारक्षित, सुपरफास्ट सेवा
- ❑ दीन दयालु सवारी डिब्बे– पेयजल और बड़ी संख्या में मोबाइल चार्जिंग के पांइटों वाले अनारक्षित सवारी डिब्बे

आरक्षित यात्रियों के लिए

- ❑ हमसफ़र–पूर्णतः वातानुकूलित 3 एसी सेवा जिसमें भोजन के विकल्प की सेवा मौजूद हो।
- ❑ तेजस–तेजस भारत में रेलगाड़ी यात्रा के भविष्य को दिखाएगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे अधिक गति पर चालित, ये जवाबदेही और उन्नत ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए एक सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनबोर्ड सेवाएं पेश करेगी जैसे मनोरंजन, स्थानीय भोजन, वाई–फाई आदि। टैरिफ और नॉन–टैरिफ उपायों के माध्यसम से लागत की वसूली सुनिश्चित करने के लिए हमसफ़र और तेजस
- ❑ उदय– सबसे व्यस्तम मार्गों पर रात्रिकालीन डबल डेकर, उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकुलित यात्री एक्सप्रेस जिससे वहन क्षमता के लगभग 40 प्रतिशत बढ़ाने की सम्भावना हैं।

MOBILE TOWER RADIATION APPEARS TO HAVE NO 'ADVERSE HEALTH EFFECTS': TRAI

Telecom Regulatory Authority of India (Trai) experts have claimed that radiation from electro-magnetic fields (EMF) of mobile towers does not appear to have "adverse health effects" either on adults or on children in the country.

"A number of judgements delivered by the High Courts in Gujarat, Kerala, Allahabad, Delhi and Himachal Pradesh have ruled that there is no conclusive evidence to prove that EMF radiation emitted from mobile towers has adverse effects on health. Thus, they cannot potentially harm humans," Trai Advisor (B&CS) Agneshwar Sen said.

The emission levels in the country are kept at 1/10th of the global standards recommended by International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection and recognised by the World Health Organisation, the experts said during an interactive session on Effects of EMF Radiation on Human Health in Kolkata on Monday.

"The EMF penalty norm that has been set by the Department of Telecom (DoT) as on November 2013 levies a penalty of Rs. 10 lakh per tower site per telecom service provider if they fail to comply with the set standards," Trai Principal Advisor Suresh Kumar Gupta said."Trai and DoT have implemented stringent emission norms that ensure no adverse effects on human health from mobile tower emissions," he said.The Telecom Enforcement, Resource and Monitoring (TERM) cell is mandated to test the level of EMF radiations of 10 percent of the total number of base stations and roof top towers per year.

In West Bengal Circle, such violation was observed only at Siliguri's Prakesh Nagar which was rectified by increasing the height of tower, its officer Supriyo Dutta said.

Trai, Gupta said, has recommended merger of acquisitions and spectrum sharing to provide quality service to the continuously expanding figures of almost one billion mobile subscribers in the country.

"This is because the need for more and more towers and quality infrastructure is increasing exponentially in the present age of high demand for data and mobile Internet service," he added.

Sen said the dearth of adequate number of mobile towers was one of the reasons for deteriorating quality of mobile services in the country. A number of state government officials, city municipal bodies, resident welfare associations, NGOs, consumer fora, builders, academicians and telecom service providers participated in the interactive session held in the city.

SHREE MAHESH SEWA SAMITI-BHILWARA STARTS A GIRLS PUBLIC SCHOOL MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL

Since its inception, the samiti has grown multifariously high in number of parents associated and success stories by students, ranging from top bureaucrats, affluent business leaders, dominant political personalities to all spheres of human endeavour and establishment.

Presently society is having more than 3000 students studying at schools run by shree Mahesh seva samiti i.e. Mahesh shiksha sadan (Permanently affiliated to RBSE Sr. Sec. Schol), Shree Mahesh Public School (CBSE affiliated Sr. Sec. School) Mahesh ITI (Registered and recognized by Technical education system, Rajastha) and Shree Mahesh Primary school.

Considering the present scenario and demand society is been successful in establishing a girls educational institute in Bhilwara, where international standard education with all facilities of technology, expertise can be delivered to girl child of society. The committee has started an state of art educational institute for girls at Sector-G, Azad Nagar-Bhilwara by name Maheshwari Public School (MPS –Bhilwara) and it has been envisioned to get school affiliated to CBSE upto 12th standard with all subjects, also for the competitive international scenario foreign affiliation like Cambridge, IB have also been taken into consideration.

In establishing this institute committee has categorically kept in mind that girls of the society are needed to be empowered rigorously and developed robustly so that in the days coming she can stand firm and face the world with integrity and dignity, where she is able to keep her pride intact and deal with adversaries with ease, for that facilities of training from very early days has been conceptualized, along with means of achieving academic excellence are kept at her near.

At Maheshwari Public School (MPS –Bhilwara) every class room has been fitted with modern means of technology of master class in which entire contents and software development is done by team of MPS-Girls which makes it the first school of Rajasthan to do so, also 24X7 connectivity with parents have also been arranged as an open plate from for their say, the examination system and teaching methodology have been systemized best as activity based in which a very least pressure is transferred to children or parents, students achieve their success at very ease.

GUIDELINES FOR FIILING THE ONLINE UDYOG AADHAAR FORM

A. **EM-I has been abolished.**

B. Udyog Aadhaar (UA) is for running units. No need to apply for upcoming units.

1. Aadhaar Number - 12 digit Aadhaar number issued to the applicant should be filled in the appropriate field.

2. Name of Owner- The applicant should fill his/her name strictly as mentioned on the Aadhaar Card issued by UIDAI. E.g. if Raj Pal Singh has his name as Raj P. Singh, the same should accordingly be entered if the name does not match with the Aadhar Number, the applicant will not be able to fill the form further.

To Validate Aadhar -

1. Validate Aadhar- The applicant must click on Validate Aadhaar button for verification of Aadhaar, after that only user can fill the form further.
2. Reset- The applicant can click on reset button to clear the field of Aadhaar No and Name of the owner for different Aadhaar.

3. Social Category- The Applicant may select the Social Category (General, Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Castes (OBC). The proof of belonging to SC, ST or OBC may be asked by appropriate authority, if and when required.

4. Name of Enterprise- The Applicant must fill the name by which his/her Enterprise is known to the customers/public and is a legal entity to conduct business. One applicant can have more than one enterprises doing business and each one can be registered for a separate Udyog Aadhaar and with the same Aadhaar Number as Enterprise 1 and Enterprise 2 etc.

5. Type of Organization- The Applicant may select from the given list the appropriate type of the organisation for his/her enterprise. The Applicant must ensure that he/she is authorised by the legal entity (i.e. enterprise being registered for Udyog Aadhaar) to fill this online form. Only one Udyog Aadhaar number shall be issued for each enterprise.

6. Postal Address- The Applicant should fill in the appropriate field the complete postal address of the Enterprise including State, District, Pin code, Mobile No and Email.

7. Date of Commencement- The date in the past on which the business entity commenced its operations may be filled in the appropriate field.

8. Previous Registration Details(if any)- If the Applicant's enterprise, for which the Udyog Aadhaar is being applied, is already issued a valid EM-I/II by the concerned GM (DIC) as per the MSMED Act 2006 or the SSI registration prevailing prior to the said Act, such number may be mentioned in the appropriate place.

9. Bank Details- The Applicant must provide his/her bank account number used for running the Enterprise in the appropriate place. The Applicant must also provide the IFS Code of the bank's branch where his/her mentioned account exists. The IFS code is now a days printed on the Cheque Books issued by the bank. Alternatively, if the Applicant knows the name of the Bank and the branch where his/her account is there, the IFSC code can be found from website of the respective Bank.

10. Major Activity- The major activity i.e. either "Manufacturing" or "Service" may be chosen by the enterprise for Udyog Aadhaar.

11. NIC Code- The Applicant may choose as appropriate National Industrial Classification-2008 (NIC) Code for the selected "Major Activity". The NIC codes are prepared by the Central Statistical Organisation (CSO) under the Ministry of Statistics and Program implementation, Government of India..

12. Person employed- The total number of people who are directly been paid salary/ wages by the enterprise may be mentioned in the appropriate field.

13. lnvestment in Plant & Machinery / Equipment- While computing the total investment , the original investment (purchase value of items) is to be taken into account excluding tho cost of pollution control, research and development, industrial safety devices, and such other items as may be specified, by notification of RBI. If an enterprise started with a set of plant and machinery purchased in 2008 worth Rs. 70.00 lakh has procured additional plant and machinery in the year 2013 worth Rs. 65.00 lakh, then the total investment in Plant & Machinery may be treated as Rs. 135.00 lakh.

14. DIC- The Applicant, based on the location of the Enterprise, has to fill in location of DIC. This Column will be active and show option only when there are more than one DIC in the district. In fact if there is only one DIC in the district system will automatically register you in the same DIC.

15. Submit- The Applicant must click on Submit button to generate acknowledgment number.

PRADHAN MANTRI MUDRA LOAN BANK YOJANA (PMMY)

It has been the strongest endeavor of the Prime Minister Narendra Modi to bank the unbanked population. He, in all his addresses emphasizes the importance of bringing the unbanked people under the mainstream banking in order to make the neglected section of population self reliant and self dependent. Mudra Bank Loan yojana comes as a vision from the Prime Minister by the slogan, 'Fund the Unfunded'. MUDRA means Micro Units Development and Refinance Agency. This initiative has been started after the success of PM Jan Dhan Yojana.

Population engaged in small businesses always requires micro finance to facilitate their business and day to day business needs. PM Mudra Bank Yojana would help in facilitating micro credit up to Rs 10 lakh to such small business owners. PM Mudra Bank already has a corpus of more than Rs 70,000 CR and this amount would help in increasing the overall output and creating newer jobs.

The recovery method under pradhan mantri mudra yojana

Mudra Bank would work on both ends, as per the scheme. It would ensure that proper and adequate credit facility is facilitated to the needy entrepreneurs on one hand, whereas, accurate and efficient recovery method is followed by the banks on the other, to create a justifiable and balanced credit system. You will have to repay the loans taken in a tenure ranging from 5 to 7 years.

The stages and reach of loan under pradhan mantri mudra yojana

There are three main stages of PM Mudra Bank Yojana:

Sr.	Stages	Maximum Amount	Details
1	Shishu	Rs 50 Thousand	This stage would cater to entrepreneurs who are either in their primitive stage or require lesser funds in order to get their businesses started. Under this stage the applicant would be eligible to get up to Rs 50,000 credit.
2	Kishor	Rs 5 Lakhs	This stage would cater to entrepreneurs who have requirement of funds in the range of Rs 50,000 and Rs 5 lakh. This section of entrepreneurs would belong to either those who have already started their business and want additional funds to mobile the business or those who simply require this much of money to start up their businesses.
3	Tarun	Rs 10 Lakhs	If an entrepreneur meets the required eligibility conditions, he/she could apply for a loan up to Rs 10 lakh. This would be the highest level of amount that an entrepreneur could apply for a start up loan.

What you should know about Pradhan Mantri Mudra Yojana

Apart from what we have already informed about PM Mudra Bank, following are the things that you should know as well:

1. The Pradhan Mantri Mudra Bank Yojana is said to benefit more than 58 million small business owners in the country. This is one sector under which more than 120 million people are employed and this working population mostly comes from less privileged sections of society.
2. The majority of small businesses owners in India have always remain outside the ambit of mainstream bank credit. This is just because banks and financial institutions often focus their products and services for the secured business lot, who would repay at higher interest and have their monies secured. PM Mudra bank yojana would help in getting this trend changed.
3. Institutional finance has always been relevant to small businesses. However, inadequate corpus and unorganized management of credit facility to small entrepreneurs never really made it reach the need entrepreneurs. A PM Mudra bank yojana comes with a dream to get the dreams of many young and budding entrepreneurs fulfilled.
4. Repayment has always been a concern why financial institutions could not provide required finance to small business owners. With this initiative from the PM office, the scheme is said to take care of this part as well and thus help both financial institutions and needy small business owners come on one single platform.

You can Download Mudra application Form

Mudra Loan Yojana Interest Rate

Many people have started inquiring about the Mudra Loan Interest. We have got some clarification on this, interest rate wont be fixed and would depend on the type of your business and the bank. Each bank will have their own criteria.

Government may give some subsidy on the interest but the percentage is still not declared. Details on this could be found more on the official site http://www.mudra.org.in/

We have just heard that corporation bank has offered Mudra Loan at interest rate of 11-12%.

How to apply Mudra Loan

There is no formal or structured way of apply Mudra Loan. You will have to approach all the banks listed in this blog and give them the detailed description of your business. Then will ask to to fill the Mudra form. If you already have a current account in that bank then it will help your application to process quickly. If you need any equipment for your business please carry the invoice for the same. This is a collateral free loan so if you have a good credit history then it would help. Please take the acknowledgement slip with you for reference.

इंस्टीट्युट ऑफ कॉस्ट अकॉउन्टेंट्स का आइकन ऑफ ईयर अवार्ड श्री नौलखा को

भीलवाड़ा के कॉस्ट अकॉउन्टेंट्स एवं उद्योगपति श्री आर एल नौलखा को विज्ञानं भवन नई दिल्ली में वर्ष 2015 का आइकन ऑफ़ ईयर का अवार्ड देश के केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रदान किया। अजमेर भीलवाड़ा चेप्टर ऑफ़ कॉस्ट अकॉउन्टेन्ट्स के चेयरमैन श्री वी के गोयल से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली बार भीलवाड़ा के किसी कॉस्ट अकॉउन्टेन्ट्स को यह अवॉर्ड मिला है। कार्यक्रम के अंतिम सत्र को इजिप्ट के वाणिज्य दूत के मंत्री श्री मोंगी अल बदर ने सम्बोधित किया। उल्लेखनीय है कि मेवाड चेम्बर के पूर्वाध्यक्ष श्री आर एल नौलखा जाने माने प्रोफेशनल कम उद्योगपति है। श्री नौलखा सीए, सीएस एवं कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स है।

INTEREST EQUALISATION SCHEME ON PRE AND POST SHIPMENT RUPEE EXPORT CREDIT

RBI/2015-16/322

DCBR.CO.SCB.Cir. No. 1/13.05.000/2015-16 February 11, 2016

The Government of India has announced the Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit to eligible exporters. The scheme is effective from April 1, 2015. The details of the scheme are enclosed.

2.Accordingly, scheduled Urban Cooperative Banks holding AD Category I licencesare eligible under the Scheme and are advised to adhere to the following operational procedure for claiming reimbursement:

A. Procedure for passing on the benefit of interest equalisation to exporters:

(i) For the period April 1, 2015 to January 31, 2016 banks shall identify the eligible exporters as per the Government of India scheme and credit their accounts with the eligible amount of interest equalisation.

(ii) From the month of February 2016 onwards, banks shall reduce the interest rate charged to the eligible exporters as per our extant guidelines on interest rates on advances by the rate of interest equalisation provided by Government of India.

(iii) The interest equalisation benefit will be available from the date of disbursement up to the date of repayment or up to the date beyond which the outstanding export credit becomes overdue. However, the interest equalisation will be available to the eligible exporters only during the period the scheme is in force.

B. Procedure for claiming reimbursement of interest equalisation benefit already passed on to eligible exporters:

(i) The sector-wise consolidated reimbursement claim for the period April 1, 2015 to January 31, 2016 for the amount of interest equalisation already passed on to eligible exporters should be submitted to RBI by February 29, 2016.

(ii) The sector-wise consolidated monthly reimbursement claim for interest equalisation for the period February 2016 onwards should be submitted in original within 15 days from the end of the respective month, with bank's seal and signed by authorised person, in the prescribed format given in Annex I.

(iii) The claims should be accompanied by an External Auditor's Certificate (with stamp and membership number) certifying that the claim for interest equalisation of Rupees…….. for the month ended …….. has been verified and found to be strictly in accordance with the provisions of the Government scheme enclosed with the circular DCBR.CO.SCB.Cir. No.1/13.05.000/2015-16 dated February 11, 2016. Claims for reimbursement will be considered for settlement only after receipt of this certificate.

(iv) The claims may be submitted to the Principal Chief General Manager, Department of Cooperative Bank Regulation, Reserve Bank of India, Central Office, C-7 Bandra Kurla Complex, 1st and 2nd Floor, Bandra (East), Mumbai – 400051.

(v) The reimbursement of interest equalisation claim will be made as and when the funds are received from Government of India.

Yours faithfully
(Suma Varma)
Principal Chief General Manager

REGARDING-AMENDMENT IN PAYMENT OF BONUS ACT W.E.F. 1.04.2014

Please note that Kerala High Court granted Stay for amending the Payment of Bonus Act to pay to person for salary up to 21,000/- and Bonus to be calculated at salary of 7,000/- per month made effective from 1.04.2014 as per order issued dated 31.12.2015, members may also approach the Hon'ble High Court for similar stay.

IN THE HIGH COURT OF KERALA AT ERNAKULAM

:Present:

THE HONOURABLE MR.JUSTICE V, CHITAMBARESH

Wednesday, the 27th day of January 2016/7th Magha, 1937

WP(C).No.3025/20l6 (C)

PETITIONERS/

1. THE UNITED PLANTERS' ASSOCIATION OF SOUTHERN INDIA, 'GLENVIEW', COONOOR, NILGIRIS DISTRICT, TAMIL NADU, REPRESENTED BY ITS SECRETARY GENERAL SRI ULLAS MENON.
2. S.B.PRABHAKAR,
   SHOLAYAR ESTATE, PAMPADAMPARA GROUP OF ESTATES PAMPADAMPARA P.O., IDUKKI DISTRICT.

RESPONDENTS/

UNION OF INDIA, REPRESENTED BY THE SECRETARY TO GOVERNMENT MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

SHRAM SAKTHI BHAVAN, RAFI MARG, NEW DELHI-110 001

Writ Petition (civil) praying inter alia that in the circumstances stated in the affidavit filed along with the WP(C) the High Court be pleased to stay the operation and implementation of the Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015, pending disposal of the Writ Petition (Civil) .

This petition coming on for admission upon perusing the petition and the affidavit filed in support of WP(C) and upon hearing the arguments of SRI. E. K. NANDAKUMAR, Senior Advocate along with M/S. M.GOPIKRISHNAN NAMBIAR, P.GOPINATH MENON, BENNY P.THOMAS, K.JOHN MATHAI, JOSON MANAVALAN, KURYAN THOMAS, Advocates for the petitioner and of SRI. A. R. GANGADAS, Central Government Counsel for the respondent, the court passed the following:

ORDER

Admit.

Mr. A. R. Gangads Central Government Counsel takes notice for the respondent:

Ext. P1 amendment to the extent it gives retrospective effect from 01.04.2014 is hereby stayed. Ext. P1 amendment in other words shall be implemented from 2015-16 pending disposal of the writ petition.

27-01-2016

Sd/- V.CHITAMBARESH, JUDGE

true copy

ASSISTANT REGISTRAR

Exhibit-P1 : TRUE COPY OF THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ACT, 2015 PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA NOTIFIED IN THE GAZETTE OF INDIA ON THE 1ST JANUARY 2016.

Government of India
Ministry of Finance (Department of Revenue)
New Delhi

NOTIFICATION NO 06/2016-Service Tax, Dated: February 18, 2016

In exercise of the powers conferred by section 109 of the Finance Act, 2015 (No. 20 of 2015), the Central Government hereby appoints the 1 st day of April, 2016 as the date on which the provisions of sub-section (1) of section 109 of the said Act shall come into effect.

[F. No. B-1/10/2015 - TRU]
(K Kalimuthu)
Under Secretary to the Government of India

Contributed By Shri Anil Mishra,
J.K.Tyre & Industries Ltd, Kankroli

बजट पूर्व वैट बढोतरी

फरवरी 2016 में राज्य सरकार ने 5 प्रतिशत वैट दर को आधा प्रतिशत और बढ़ा दिया। इसका सीधा असर भीलवाड़ा की हजारों वीवींग एवं प्रोसेसिंग इकाइयों पर पड़ेगा। प्रदेश के बाहर से आने वाले यार्न पर केवल दो प्रतिशत एंट्री टैक्स है जबकि प्रदेश से प्रदेश में ही यार्न खरीदने पर साढ़े पांच प्रतिशत वैट हो जाने से यहां के स्पिनिंग मिलों पर दोहरी मार पड़ रही है। प्रदेश के बाहर से आने वाले यार्न पर एक प्रतिशत ट्रांसपोर्ट खर्च भी मान लिया जाए तो पहले यहां के कपड़ा उद्यमी प्रदेश के बाहर की स्पिनिंग मिलों से दो प्रतिशत फायदे पर यार्न खरीदना पसंद कर रहे थे। यहां के स्पिनिंग मिलों की स्थानीय खपत करीब 40 प्रतिशत ही है। बाहर का यार्न सस्ता मिलने के कारण करीब 60 प्रतिशत वीवर्स यार्न बाहर की मिलों से ही खरीदते हैं। प्रदेश से प्रदेश में यार्न खरीदने पर अब आधा प्रतिशत वैट और बढ़ने से स्थानीय स्पिनिंग मिलों की खपत और कम हो जाएगी क्योंकि कपड़ा उद्यमी ढाई प्रतिशत फायदे पर बाहर से ही यार्न खरीदना पसंद करेंगे।

प्रोसेसहाउसों में भी डाई, केमिकल और स्पेयर पाट्र्स पर वैट पांच से बढ़ाकर साढ़े पांच प्रतिशत कर दिया गया है। यहां के प्रोसेस हाउसों पर सालाना करीब एक करोड़ रुपए का भार बढ़ गया है। वीविंग इंडस्ट्री में काम आने वाले स्पेयर पाट्र्स पर भी आधा प्रतिशत वैट बढ़ने के कारण वीविंग इंडस्ट्री पर भी करीब एक करोड़ रुपए का भार बढ़ गया है।

यार्नपर टेक्सटाइल उद्यमी लंबे समय से वैट पांच से घटाकर दो प्रतिशत करने की मांग कर रहे थे। बजट में यह कम होने की उम्मीद भी थी लेकिन राज्य सरकार ने वेट बढोतरी कर कारोबारियों को तगड़ा झटका दे दिया।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, dated: February 01,2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule IV appended to the Act, with effect from 02.02.2016, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule IV appended to the said Act-

(i) for the existing expression "GOODS Taxable at 5%", the expression "GOODS TAXABLE AT 5.5%" shall be substituted;

(ii) in column number 3, for the existing expression "5", wherever occurring, the expression "5.5" shall be substituted;

(iii) in column number 3 of Part-A GOODS UNDER CATEGORY OF IT PRODUCTS, for the existing expression "5", wherever occurring, the expression "5.5" shall be substituted; and

(iv) in column number 3 of Part-B GOODS UNDER CATEGORY OF INDUSTRIAL INPUTS, for the existing expression "5", wherever occurring, the expression "5.5" shall be substituted.

[No. F. 12(42)FD/Tax/2010-123]
By order of the Governor
(Dr. Devraj)
Joint Secretary to Government

FICCI RAJASTHAN STATE COUNCIL

Mr Ashok Kajaria, Chairman and Managing Director, Kajaria Ceramics Ltd has been appointed as the Chairman of FICCI Rajasthan State Council.

Mr Raman Kumar Sharma, Sr Vice President & Director, Honda Cars India Ltd and Mr Randhir Vikram Singh, Joint Managing Director, Mandawa Hotels have been appointed as Co-Chairmen.

Our heartiest goodwishes to them

वजन कम करने के लिए जीरा उपयोगी

वजन कम करने के लिए लोग क्या–क्या नहीं करते, घंटों तक व्यायाम करना, खान–पान कम कर देना और पसंदीदा चीज़ ही ना खा सकना। इसके बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हासिल होता उन्हें, लेकिन अब जीरा वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। खाने के स्वाद को बढ़ाने वाला जीरा, खासतौर से दाल में डालने वाला जीरा हर किसी को पसंद है। कुछ लोग चावल पकाते समय भी जीरे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके खुशबू भी काफी अच्छी लगती है जो पकवान की सुगंध को बढ़ा देती है।

मसाला मात्र नहीं

लेकिन खाद्य पदार्थों के गुणों को बढ़ाने वाला मसाला मात्र नहीं है जीरा, इसके गुण तो अनेक हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं, जिसमें से विशेष है जीरा के प्रयोग से वजन कम करने की प्रक्रिया। एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि जीरा पाउडर के सेवन से शरीर मे वसा का अवशोषण कम होता है जिससे स्वाभाविक रूप से वजन कम करने में मदद मिलती है।

बीमारियों से भी बचाता है

वजन कम करने के साथ साथ यह बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी बचाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, खून की कमी को ठीक करता है, पाचन तंत्र ठीक कर गैस और ऐंठन ठीक करता है। तो यदि उपरोक्त बताई परेशानी किसी को है, तो रोज़ाना जीरा का प्रयोग भोजन पकाते समय अवश्य करें।

स्वास्थ्य को मिलने वाले लाभ

लेकिन जीरा के प्रयोग से स्वास्थ्य को मिलने वाले जिस खास लाभ की यहां हम बात करने जा रहे है, वह है वजन कम करना, और वह भी मात्र 15 दिनों में। जी हां.... जो काम बड़े से बड़ा प्रयोग करने में अक्षम है, वह जीरा का एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाएगा। बस निर्देशानुसार आप इसका प्रयोग करें तो जरूर सफल होंगे।

दो बड़े चम्मच जीरा एक गिलास पानी मे भिगो कर रात भर के लिए रख दें। सुबह इसे उबाल लें और गर्म–गर्म चाय की तरह पियें। बचा हुआ जीरा भी चबा लें। इसके रोजाना सेवन से शरीर के किसी भी कोने से अनावश्यक चर्बी शरीर से बाहर निकल जाती है।

दूसरा प्रयोग

किंतु यदि आपको यह प्रयोग अधिक पसंद ना आए, तो जीरे को खाद्य पदार्थ में अच्छी मात्रा में प्रयोग करें और रोज़ाना इस्तेमाल करें। एक अन्य उपाय के अनुसार आप 50 ग्राम दही में एक चम्मच जीरा पाउडर मिलाकर यदि इसका रोज़ाना सेवन करें, तो वजन जरूर कम होगा।

यकीनन आपका वजन 15 दिनों के पश्चात कम होता दिखाई देगा। विशेषज्ञों के अनुसार जीरे में मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीकडेंट चयापचय को बढ़ाता है, जिससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। यह चर्बी ही तो मोटापे को दावत देती है, जो जीरे के प्रयोग से खत्म की जा सकती है।

हार्ट के मरीजों के लिए सही

हार्ट के मरीजों के लिए भी बेहद फायदेमंद है यह जीरा, जीरा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही फैट को शरीर में बनने से रोकता है। इसलिए यह वजन कम करने में मदद करता है साथ ही हार्ट अटैक से भी बचाता है।

अन्य फायदे

इसके अलावा जीरा खाने को पचाने में मदद करता है जिससे गैस कम बनती है। ऐंठन और पेट फूलना ख़राब पाचन की समस्या हैं। जीरा गैस को बनने से रोकता है जिससे पेट और आंतों में अच्छे से खाना पच जाता है।

चलिए यह तो रही सेहत की बात, लेकिन जीरा सौंदर्य भी निखारेगा यह नहीं जानते होंगे आप। दरअसल जीरे में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी त्वचा पर पड़े विभिन्न दाग–धब्बों को हल्का करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा त्वचा का काला पड़ जाना या मुरझा जाना, आदि समस्याओं को हल भी जीरे के कुछ घरेलू नुस्खों से हासिल किया जा सकता है।

जीरे में विटामिन ''ई'' पाया जाता है, जो त्वचा के लिए काफी लाभदायक होता है। इसके अलावा जीरे में कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो त्वचा को संक्रमण रहित बनाते हैं। यदि किसी के चहरे पर कोई दाग–धब्बे, पिंपल या किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन हो गया हो, तो थोड़ा–सा जीरा पीसकर किसी भी फेस पैक में मिलाकर लगा लें, जल्द से जल्द आराम मिलेगा।

With Best Compliments From

sona

Sona Processors (India) Ltd.

: Works :

NH – 79, 12 K.M. Stone, Village – Guwardi
Chittor Road, Bhilwara - 311025
E-mail: sonaprocess@gmail.com
Phone : +91-1482 249040 – 43 Fax : + 91- 1482 249044

Regd. Office : 2, Sangam Tower, Old RTO Road
Gandhi Nagar, Pur Road, Bhilwara 311 001 (Raj.)
E-mail : info@sonaprocessors.com
Phone : +91-1482 246530, 246585

पोस्टल रजि नं. भीलवाड़ा/254/2015–2017 प्रेषणः प्रत्येक माह की 7 तारीख अधिकृत डाकघरः प्रधान डाकघर, भीलवाड़ा

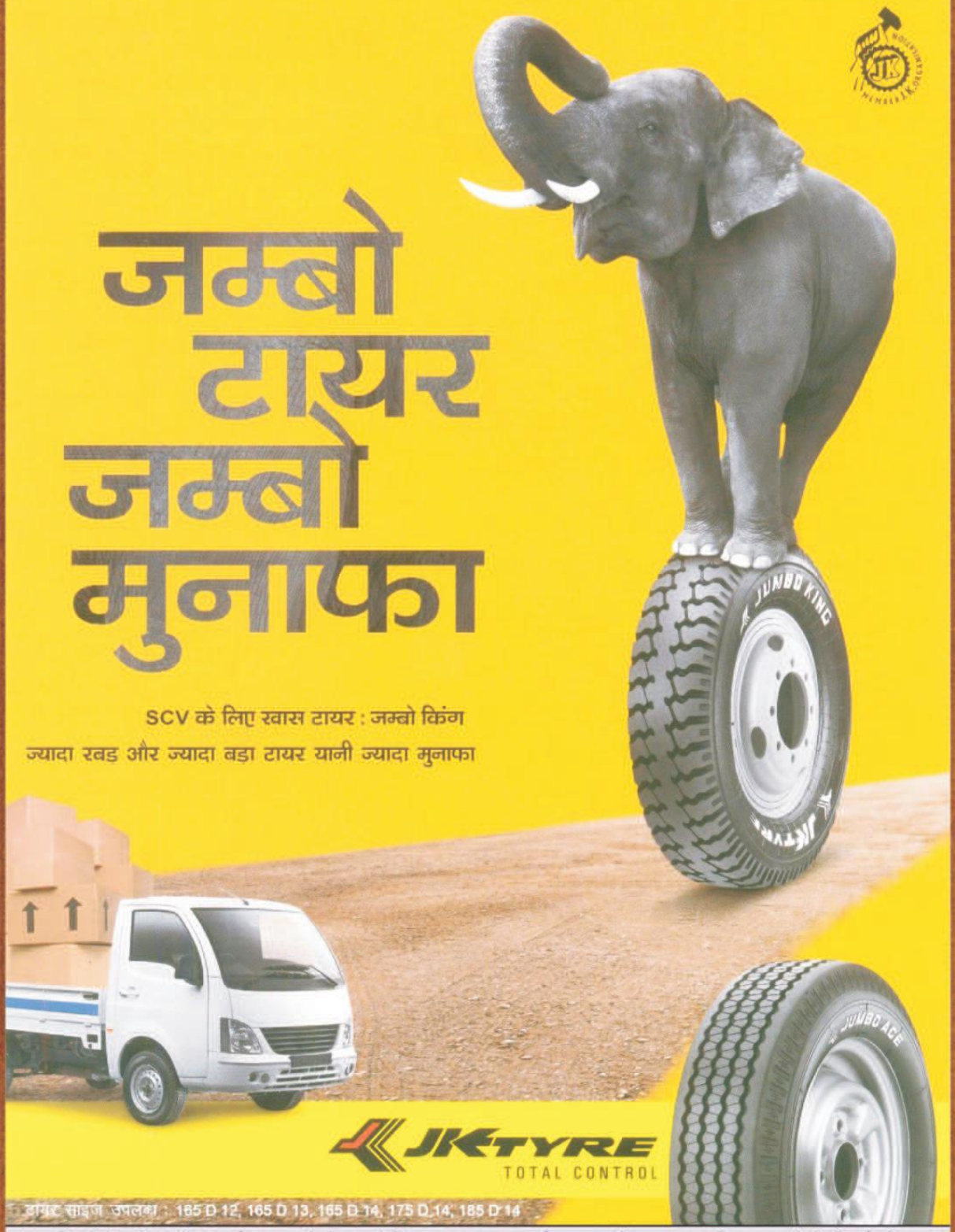

स्वत्वाधिकारी मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री भीलवाड़ा के लिए सम्पादक-प्रकाशक सूर्यप्रकाश नाथानी द्वारा अलका ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, भीलवाड़ा से मुद्रित एवं मेवाड़ चेम्बर भवन नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा से प्रकाशित। सम्पादक-सूर्यप्रकाश नाथानी फोन : 01482–220908 (ऑ.)